Registered with the Registrar of News Paper (Govt. of India) Vide R.N.I. No. 39299/81

On The Way Half Century 50

मूल्य एक प्रति 3.00 रु.
Monday & Tuesday every week on Delhi Postal Regd. No. DL(E)-20/5174/2021-23

व्यापार एक्सप्रेस

(हिन्दी साप्ताहिक)

Office : 2718, Street No. 5, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032
Mob.: +91-9312625326, 9717513928
Email: vyaparexpress50@gmail.com, vyaparexpress@ymail.com

CHIEF EDITOR : T.R. ARORA
www.vyaparexpress.co

वर्ष 42 अंक 04 • 31 जनवरी 2022 — 06 फरवरी 2022 | प्रकाशन की तिथि हर सोमवार | वार्षिक मूल्य सप्लीमेंट्री सहित 1100/— पृष्ठ—4

वैश्विक उत्पादन में कमी के अनुमान से सोयाबीन के औसत भाव में बढ़ोत्तरी

अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक तिलहन के उत्पादन में कमी आने का अनुमान जताया है। दक्षिण अमरीका में सूखे मौसम की वजह से सोयाबीन की यील्ड और उत्पादन में खासी कमी आने का अंदेशा है। ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरुग्वे में सोयाबीन की पैदावार घटने की आशंका से वर्ष 2021–22 में समूची दुनिया में तिलहन का उत्पादन एक फीसदी से ज्यादा घटने की संभावना है।

समूची दुनिया में तिलहन का उत्पादन 61.91 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो बीते महीने 62.75 करोड़ टन था। तिलहन का वैश्विक अंतिम स्टॉक ब्राजील, अर्जेंटीना में सोयाबीन की उपज घटने से छह फीसदी गिरने के आसार हैं। यूएसडीए ने सोयाबीन का औसत दाम वर्ष 2021–22 के लिए 50 सेंटस बढ़ाकर 12.60 डॉलर प्रति बुशेल पर कायम रखा है।

यूएसडीए ने वर्ष 2021–22 में समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन 37.25 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है, यह अनुमान पिछले महीने 38.17 करोड़ टन था। जबकि वर्ष 2020–21 में समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन अनुमान 36.62 करोड़ टन और वर्ष 2019–20 में यह 33.98 करोड़ टन था।

वर्ष 2021–22 में अमरीका में सोयाबीन उत्पादन अनुमान 12.07 करोड़ टन आंका है जो वर्ष 2020–21 में 11.47 करोड़ टन रहा। वर्ष 2019–20 में यह 9.66 करोड़ टन था। ब्राजील में वर्ष 2019–20 में सोयाबीन उत्पादन 12.85 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2020–21 में 13.80 करोड़ टन रहा। जबकि, वर्ष 2021–22 में इसके 13.90 करोड़ टन रहने की संभावना है। अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 4.88 करोड़ टन रहा जिसके वर्ष 2020–21 में 4.62 करोड़ टन एवं वर्ष 2021–22 में 4.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

चीन में सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 1. 64 करोड़ टन और वर्ष 2020–21 में 1.96 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीन में वर्ष 2019–20 में सोयाबीन का उत्पादन 1.80 करोड़ टन रहा। यूएसडीए का कहना है कि वर्ष 2021–22 में चीन का सोयाबीन आयात वर्ष 2020–21 के 10 करोड़ टन रहने की संभावना है। यह आयात वर्ष 2019–20 में 9.97 करोड़ टन रहा।

बासमती चावल के निर्यात में 18 से 20 फीसदी की कमी आने की आशंका

घरेलू मंडियों में धान की नई फसल की आवक अब कम होने लगी है, जबकि आमतौर पर नवंबर से जनवरी के दौरान बासमती चावल के सबसे ज्यादा निर्यात सौदे होते है लेकिन चालू सीजन में ईरान के साथ ही इराक की आयात मांग सामान्य की तुलना में कम आने से घरेलू बाजार में महीनेभर में धान के साथ ही चावल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है।

सूत्रों के अनुसार, घरेलू मंडियों में पूसा 1,121 किस्म के धान के भाव पिछले दिनों बढ़कर 3,900 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और ट्रेडिशनल बासमती के बढ़कर 4,300 से 4,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गए थे। इस समय उत्पादक मंडियों में पूसा 1,121 बासमती धान के भाव 3,600 से 3,800 रुपये क्विंटल चल रहे हैं। इसी तरह से उत्पादक राज्यों में पूसा 1,121 किस्म के स्टीम चावल के दाम 7,400 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं, जबकि पिछले दिनों इसके भाव 8,200 से 8,300 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गए थे। चालू वित्त वर्ष में जहां गैर बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, वहीं बासमती चावल के निर्यात में 18 से 20 फीसदी की कमी आने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार, अनुसार ईरान के साथ ही इराक की आयात मांग कमजोर होने से बासमती चावल के कुल निर्यात में कमी आने की आशंका है।

हालांकि सऊदी अरब की बासमती चावल में इस समय आयात मांग अच्छी है तथा सूत्रों के अनुसार, आगे ईरान और इराक के साथ ही अन्य देशों की आयात मांग भी बढ़ेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2021–22 के पहले आठ महीनों अप्रैल से नवंबर तक देश से बासमती चावल का निर्यात 24.02 लाख टन का और गैर बासमती चावल का निर्यात 108.82 लाख टन का हुआ है। मूल्य के हिसाब से बासमती चावल का निर्यात अप्रैल से नवंबर के दौरान 15,305.59 करोड़ रुपये का और गैर बासमती चावल का निर्यात 28,932.78 करोड़ रुपये का हुआ है। नवंबर में देश से जहां 2.39 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हुआ है, वहीं इस दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 12.52 लाख टन का हुआ है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान देश के बासमती चावल का निर्यात 46. 31 लाख टन का और गैर बासमती चावल का 130.87 लाख टन का हुआ था।

चीनी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समिति के निर्णय के खिलाफ भारत ने की अपील

भारत ने घरेलू चीनी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार विवाद समाधान समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करते हुए कहा है कि उसने समिति ने कानून से जुड़ी कुछ गलतियां की है। डब्ल्यूटीओ ने एक बयान में कहा कि भारत ने उसके अपीलीय निकाय के समक्ष अपील की है। व्यापार संबंधी विवादों में यह अंतिम निर्णायक संस्था है। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि, भारत ने विवाद निपटान निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील की सूचना दी है। व्यापार विवाद समाधान समिति ने यह निर्णय भारत में चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की अपीलों पर दिया था। हालांकि, इस समय अपीलीय निकाय सक्रिय स्थिति में नहीं है।

डब्ल्यूटीओ ने कहा कि उसके सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बनने से अपीलीय निकाय की भर्तियां भरी नहीं जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में भारत की अपील पर फौरन कोई निर्णय हो पाना संभव नहीं है। विवाद निपटान समिति ने गत 14 दिसंबर को अपने फैसले में भारत को घरेलू स्तर पर चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी हटाने का सुझाव दिया था। उसने कहा था कि सरकारी समर्थन देना डब्ल्यूटीओ के व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं है। इस फैसले के खिलाफ की गई अपील में भारत ने कहा है कि समाधान समिति के निर्णय एवं निष्कर्ष को पलट देना चाहिए क्योंकि इसमें कानून या कानूनी व्याख्या की खामियां रही हैं। भारत ने चीनी उत्पादन सत्र 2019–20 के लिए चीनी के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन और ढुलाई भाड़े की लागत पर चीनी मिलों को सरकारी समर्थन की योजना चलाई थी। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एवं ग्वाटेमाला ने इस कदम को डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ बताया था।

भारतीय मक्का में लगातार खरीददार

दक्षिण–पूर्व एशियाई देश, विशेष रूप से वियतनाम और मलेशिया, भारतीय मक्का को बड़े पैमाने पर खरीदना जारी रखे हैं क्योंकि इसके भाव जुलाई 2021 के ऊंचे स्तुर से नीचे आ गई है। एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि वियतनाम और मलेशिया अच्छी मात्रा में भारतीय मक्का खरीद रहे है, लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण हमें अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है। निर्यातकों के मुताबिक, वियतनाम मुर्गियों को खिलाने के लिए भारतीय मक्का का एक बड़ा खरीदार बन गया है। रुपए की मजबूती ने निर्यातकों के मार्जिन को भी प्रभावित किया है। पिछले एक महीने में भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 1. 7 फीसदी चढ़ा है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 74.4 था। इंटरकां–टिनेंटल एक्सचेंज में मक्का वायदा 6 डॉलर प्रति बुशेल से लौट आया क्योंकि ब्राजील ने दिसंबर में किए गए अनुमानों की तुलना में अपनी फसल कम होने की सूचना दी थी।

मार्च मक्का का वायदा भाव 6.11 डॉलर प्रति बुशेल पर बंद हुआ। जुलाई 2021 में चीन द्वारा इस सीजन में खपत के अनुमान को कम करने के बाद मक्का वायदा 6.6 डॉलर से नीचे गिरने से पहले 6 डॉलर आ गया था।

हैफेड को मिला 5000 मीट्रिक टन भारतीय सेला बासमती चावल का एक एक्सपोर्ट आर्डर

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को सऊदी अरब के एक प्रमुख आयातक से 5,000 मीट्रिक टन भारतीय सेला बासमती चावल का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। हैफेड के अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीजीएम सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर, 2021 में चावल के संभावित खरीदारों से मिलने के लिए वहां का दौरा किया था। जिसके बाद यह आपूर्ति आदेश प्राप्त हुआ है।

बासमती अपने विशिष्ट स्वाद और गुणों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सऊदी अरब भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा मुरीद है। यहां एक साल में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का बासमती एक्सपोर्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार, हैफेड हरियाणा सरकार का एक शीर्ष सहकारी संघ है। हैफेड राज्य के किसानों की घरेलू और विदेशी बाजार में बिक्री के लिए उनकी उपज का मूल्य वर्धन करके उनकी उपज की खरीद एवं प्रसंस्करण करके उनकी सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संघ ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया। बासमती एक्सपोर्ट में 25 प्रतिशत शेयर के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। यहां से हर साल औसतन 30,000 करोड़ रुपये का बासमती चावल निर्यात होता है।

20 हजार मीट्रिक टन बासमती धान खरीदने का निर्णय: हरियाणा सरकार के मुताबिक, नवंबर, 2021 के महीने के दौरान बासमती चावल और अन्य चावल की किस्मों के बाजार मूल्य में अचानक गिरावट आई है।

हैफेड द्वारा राज्य के किसान के हितों की रक्षा करने एवं बाजार को स्थिर करने के लिए राज्य की विभिन्न मंडियों से लगभग 20,000 मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए निर्णय लिया गया। हैफेड ने भारतीय लंबे चावल, 1121 बासमती सेला और बासमती सेला सहित विभिन्न किस्मों के 870 मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट किया है।

हरियाणा बासमती का प्रमुख उत्पादक: दरअसल, कारोबार के लिहाज से बासमती चावल की खेती भारत के सिर्फ 95 जिलों में ही हो सकती है। सात राज्यों के 95 जिलों को इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला हुआ है। इनमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसलिए यहां पेड़ पैमाने पर इस धान की खेती होती है और उसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है। जिसका किसानों को काफी लाभ मिलता है।

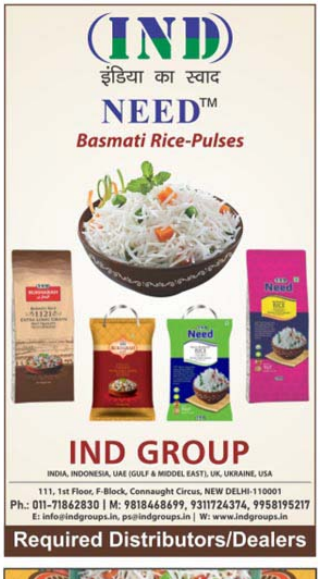

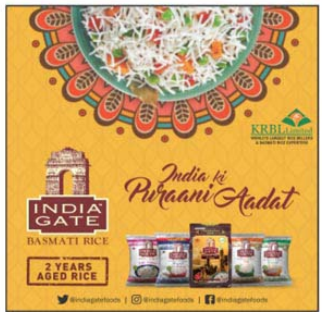

क्षेत्रीय मंडियों के बाजार भाव

कानपुरः गेहूं लूज 2150/2155, जौ 1975/2000, चावल मसूरी 2450/2550, चावल मोटा 2250/2400, देशी चना 5300/5325, चना छना 5850/5950, दाल चना 5900/6000, पिचकी 4800/5000, मटर दाल 7200/7400, अरहर लेमन 6600/6625, दाल अरहर 8900/9300, स्पेशल 8100/8400, उड़द एसक्यू 7250/7260, एफएक्यू 6600/6650, राजमा चित्रा 9900/13100, मूंग 5700/6500, मसूर छोटी 7600/7750, छांटी 8800/9300, सरसों 7300/7350, तिल सफेद 10000/10100 सोया (टीन) 2200/2250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2550/2600, सरसो खल 3300/3350, पामोलिन 2150/2200, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1950, मधुसूदन देशी घी 6200 वासुदेव 5950, परम प्रीमियम 6250 अलसी 9500/9700, धानियाः लोकल 9700/9800, राजस्थान 102000/10400

लखनऊः गेहूं दड़ा 2130/2140, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 4000/4050, स्टीम 5050/5150, लालमती 4400/3500, चावल (सोना) 4200/4300, दाल अरहर सवा नं. 7800/7900, पटका 8700/9300 रिजैक्शन 6700/7000, चना दाल 5950/6100, चना देशी छना 5950/6100, चना चापा छना 5900/6000, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत (काला) 7200/8000, दाल उड़द (काली) 7900/8900, उड़द धोया 8000/8800, मसूर छोटी 7500/7700, मलका 8500/8800, किरानाः जीरा 18400/19800 लालमिर्च गुंटूर 17500/2300, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5600/5700, धनिया एमपी 10100/12200, छोटी इलायची (किलो) 1000/1500, बडी इलायची 710/740, कालीमिर्च (किलो) 520/580, सुपारी (किलो) 580/630, सौंफ मोटी 9400/11800, मंगरैल 22500/23500, चिरौंजी (किलो) 1125/1250, मखाना 475/700

मुजफ्फरनगरः चाकू (कोल्ड) 1140/1270, खतौली 3540, देवबंद 3400, थाना भवन 3410, बुढ़ाना 3420, शामली 3390, चीनी हाजिर 3750/3850

हापुड़ः अनाज–दाल गेहूं 2215/2220, चावल परमल 2400/2450, डुप्लीकेट बासमती सेला 6100/6200, बासमती 1121 स्टीम 7400/7500, चना 5200/5250, चनादाल 5800/5900, काबली चना 7000/8500, राजमा देशी चित्रा 11500/13000, दाल अरहर 8000/8800, मसूर 7800/8000, उड़द देसी 6500/6700, दाल उड़द 7500/8500, मूंग यूपी 6500/6800, मूंग दाल 8000/9000, गुड़–चीनीः चीनी हाजिर 3800/3900

चीनी उत्पादन 2.90 प्रतिशत बढ़कर 3.19 करोड़ टन रहने का अनुमान

व्यापार संगठन एआईएसटीए के मुताबिक, ब्राजील के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में चालू विपणन वर्ष के दौरान चीनी उत्पादन 2.90 प्रतिशत बढ़कर 3.19 करोड़ टन होने का अनुमान है।

3.19 करोड़ टन के अनुमानित उत्पादन और चीनी मिलों के पास 83 लाख टन के शुरुआती स्टॉक के साथ, चालू विपणन वर्ष में देश में चीनी की कुल उपलब्धता 4.02 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है। हालांकि, देश में चीनी की आपूर्ति, घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, जो कि विपणन वर्ष 2021–22 में 2.7 करोड़ टन होने का अनुमान है।

चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। निर्यात के मामले में, अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) का कहना है कि, मौजूदा विपणन वर्ष 2021–22 में निर्यात खेप कम यानी 60 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 72 लाख टन था।

वर्ष 2021–22 में वास्तविक निर्यात, घरेलू चीनी की कीमतों के स्तर और अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतों पर निर्भर करेगा। एआईएसटीए के पहले अनुमान के मुताबिक, 2021–22 के विपणन वर्ष में देश का चीनी उत्पादन 3.19 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह 3.1 करोड़ टन था। इस वर्ष के लिए कुल अनुमानित चीनी उत्पादन में से, देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश– में चीनी मिलों का विपणन वर्ष 2021–22 में 1.05 करोड़ टन चीनी का उत्पादन करने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1.11 करोड़ टन से कम है।

हालांकि, देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन– पहले के 1.07 करोड़ टन के मुकाबले 1.15 करोड़ टन अधिक होने का अनुमान है, जबकि देश का तीसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य–कर्नाटक में चीनी उत्पादन 48 लाख टन होने का अनुमान है जो पहले 47 लाख टन था। यह अनुमान है कि चालू विपणन वर्ष में बी–हैवी शीरा और शीरे से एथेनॉल उत्पादन के लिए 31 लाख टन सुक्रोज को स्थानांतरित किया जाएगा।

एअसईएसटीए का कहना है कि, विपणन वर्ष 2021–22 में घरेलू चीनी की खपत 2 प्रतिशत बढ़कर 2.7 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2.65 करोड़ टन था। गन्ने की पेराई का काम जारी है। वह विपणन वर्ष 2021–22 के लिए फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में अपना दूसरा उत्पादन अनुमान जारी करेगा।

मक्का की उपज घटने से इसका वैश्विक उत्पादन कम रहने का अनुमान

अमरीकी कृषि विभाग का कहना है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, केन्या और मैक्सिको में वर्ष 2021–22 में मक्का की उपज घटने से इसका वैश्विक उत्पादन कम रहेगा। हालांकि, यूक्रेन और अमरीका में मक्का की पैदावार बढ़ने से इसकी कुछ भरपाई हो पाएगी। मक्का के वैश्विक कारोबार में बढ़ोतरी होगी एवं निर्यात मोर्चे की कमान यूक्रेन के हाथ होगी। जबकि, अमरीका और पेरुग्वे का निर्यात कम हरेगी।

मक्का का आयात ब्राजील, कनाडा और मैक्सिको से बढ़ेगा। यूएसडीए ने मक्का का औसत दाम वर्ष 2021–22 के लिए 5.45 डॉलर प्रति बुशेल पर कायम रखा है। दुनिया भर में वर्ष 2021–22 के लिए 120.69 करोड़ टन मक्का पैदा होने का अनुमान जताया है जबकि वर्ष 2020–21 में यह पैदावार 112.28 करोड़ टन थी। वर्ष 2019–20 में समूची दुनिया में मक्का का उत्पादन 111.97 करोड़ टन रहा। भारत में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 300 लाख टन होने का अनुमान है। यह उत्पादन वर्ष 2020–21 में 315.10 लाख टन रहा।

भारत में मक्का का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 287.66 लाख टन रहा। भारत से वर्ष 2020–21 में मक्का निर्यात 36.77 लाख टन रहा जो वर्ष 2021–22 में घटकर 25 लाख टन रह सकता है। वर्ष 2020–21 में अर्जेंटीना का मक्का निर्यात 3.65 करोड़ टन, अमरीका का निर्यात 6.85 करोड़ टन और ब्राजील का निर्यात 2.74 करोड़ टन रहा। वर्ष 2021–22 में अर्जेंटीना का मक्का निर्यात 4.15 करोड़ टन, अमरीका का निर्यात 6.15 करोड़ टन और ब्राजील का निर्यात 3.10 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यूएसडीए के मुताबिक अमरीका में वर्ष 2020–21 में मक्का का उत्पादन 35.84 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 में 38.39 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

अमरीका में वर्ष 2019–20 में मक्का उत्पादन 34.59 करोड़ टन रहा। चीन में मक्का का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 26.06 करोड़ टन रहा। जबकि, वर्ष 2021–22 में यह उत्पादन 27.25 करोड़ टन पहुंच सकता है। यूरोपीयन संघ में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 6.99 करोड़ टन पहुंच सकता है जो वर्ष 2020–21 में 6.70 करोड़ टन रहा। यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 11.50 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2020–21 में 8.70 करोड़ टन रहा।

अर्जेंटीना में मक्का का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 5.05 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 में 5.40 करोड़ टन रह सकता है। दक्षिण अफ्रीका में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 1.70 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो वर्ष 2020–21 में 1.69 करोड़ टन रहा। यूक्रेन में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 4.20 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो वर्ष 2020–21 में 3.02 करोड़ टन रहा। रुस में मक्का का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 1.38 करोड़ टन रहा जिसके वर्ष 2021–22 में 1.50 करोड़ टन रहने का अनुमान है। मैक्सिको में मक्का का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 2.76 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

समूची दुनिया में वर्ष 2020–21 में मक्का का अंतिम स्टॉक 2.92 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 के लिए 3.03 करोड़ टन आंका गया है। यह वर्ष 2019–20 में 3.06 करोड़ टन रहा।

रबी फसलों की बुआई 1.09% बढ़कर 679.34 लाख हेक्टेयर

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, चालू सीजन में जनवरी 2021 में तक रबी फसलों की बुआई 1.09 फीसदी बढ़कर 679.34 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 671.98 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

चालू रबी में दलहन की प्रमुख फसल चना और सरसों की बुआई बढ़ी है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई चालू रबी में घटकर 340.82 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 345.14 लाख हेक्टेयर से कम है। मंत्रालय के मुताबिक, तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 101.16 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 82.86 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी तिलहन की प्रमुख फसल सरसों की बुआई चालू रबी में 24.48 फीसदी बढ़कर 91 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 73.10 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। अन्य तिलहनी फसलों में सनफ्लावर की बुआई 1.12 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली की 4.65 लाख हेक्टेयर में और सफ्लावर की 73 हजार हेक्टेयर के अलावा केस्टर सीड की बुआई 2.86 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 1.02 लाख हेक्टेयर में, 4.60 लाख हेक्टेयर में, 58 हजार हेक्टेयर और 2.77 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। दालों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 164.35 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अविध इनकी बुआई 162.88 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी दलहन की प्रमुख फसल चना की बुआई चालू रबी में 3.89 फीसदी बढ़कर 113.30 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इसकी बुआई 109.05 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। मसूर की बुआई चालू रबी में 17.42 लाख हजार हेक्टेयर में, मटर की 10.10 लाख हेक्टेयर में और उड़द की 7.22 हेक्टेयर में हुई है। पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 16.87 लाख हेक्टेयर में, 10.33 लाख हेक्टेयर में और 7.80 लाख हेक्टेयर में हुई थी।

मूंग की बुआई चालू रबी में 4.67 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी की समान अवधि में इसकी बुआई 5.90 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। मोटे अनाजों की बुआई चालू रबी में 49.40 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 50.90 लाख हेक्टेयर से कम है। मोटे अनाजों में ज्वार की बुआई चालू रबी में 24.19 लाख हेक्टेयर में और मक्का की 17.83 लाख हेक्टेयर में तथा जौ की बुआई 6.78 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 27.02 लाख हेक्टेयर में, 16.31 लाख हेक्टेयर में और 6.87 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

धान की रोपाई चालू रबी में घटकर 23.61 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इसकी रोपाई 30.21 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।

किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी सरकारे

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि, केंद्र और राज्य सरकारें एकजुट होकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। सितंबर, 2018 में 'किसानों की आय दोगुना' पर एक अंतर– मंत्रालयी समिति ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सरकार ने प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय' का गठन किया है।

महामारी के दौरान भी कृषि क्षेत्र में हुई बढ़ोत्तरी: कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि, केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और भी जरूरी है। तोमर के हवाले से एक सरकारी बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें और देश के किसान एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी कृषि क्षेत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा और किसानों ने बंपर पैदावार की। गोवा में भी जब वहां का पर्यटन उद्योग ठप था, कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा।

युवाओं को कृषि की ओर कर रही आकर्षित उन्नत तकनीक: छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पीएम–किसान जैसी केंद्रीय योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए तोमर ने कहा कि केंद्र वर्ष 2027–28 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें कुल बजटीय परिव्यय 6,865 करोड़ रुपए है और इस योजना को गोवा में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस क्षेत्र में उन्नत तकनीक और नई तकनीकें राज्य में युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने लोगों से कृषि, बागवानी, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और फूलों की खेती के रूप में एकीकृत खेती करने का भी आग्रह किया।

शक्कर की कीमतों में तेजी

स्थानीय सियागंज थोक किराना मंडी में ग्राहकी सामान्य चल रही है। आगे लंबी त्योहार समय होने से ग्राहकी बढ सकती है। मसालो का सीजन है इससे मसालो में मांग का होना बताया जा रहा है। सभी कीचन मसाले के भाव में उतार चढाव होकर भाव आसमानी–सुल्तानी बने हुऐ है। तैयार पीसे मसाले पेकिंग में 250 रू से लेकर 700 रू किलो तक है। देश में यह पेकिंग मसालो की एक अजीबो–गरीब स्थिति है। सूत्रों के अनुसार, लगातार त्याहोरी सीजन रहने से आगे व्यापार सामान्य ही रहेगा। छोटे व्यापारियों के हवाले से शक्कर मिलो के और उनके शेयरो के सटटे के फायदे के लिये डिब्बा हमेशा तेजी–मंदी की राय देता रहा है ।

गत् वर्ष से शेयर बाजार का आम निवेशक कुछ कंपनियों के साथ ही शक्कर कंपनियो के शेयर पर डूबे अपने पैसे पर भारी आंसू बहा रहा है। कई निवेशक भाव नही बढने की कवायद पर शेयर छोड चुके थे। सरकार द्वारा दी गई शक्कर मिलो को राहत से अचानक इनके भाव बढने लग गये है। इस वर्ष शक्कर कंपनियो के शेयरो में भारी उछाल आया है। इसके पीछे गत् छः माह से बढे शक्कर के भाव से कंपनियो का भारी फायदा हुआ है। शक्कर भाव विगत् वर्ष से उपरी भाव 3300 से 3400 रू पर पर स्थिर बने हुऐ थे। जबकि उत्पादन 250 लॉख टन से बढते हुऐ लगभग 320 लॉख टन से उपर ही होने लगा है। गत् हप्ते शक्कर के भाव 3350 से 3400 रू से उछलते हुऐ 3600 से 3650 रू त क हो गये है । शक्कर बनने पर बाय प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल निकलता है जिसकी डिमांड पोल कंपनियों की बढते रहने से शक्कर उत्पादक कंपनिया मालामाल हाथरही है। शक्कर के भी भाव बढाने लग गये है सूत्रों के अनुसार, भारत में सबसे अधिक हाजिर व्यापार गाडियों की रही। बिगाडने में सरकारी नीति और सटटाबाजो का बोलबाला बताया जा रहा है। इससे जनता की यही राय कायम हो रही है कि शक्कर पर अब अधिक मंदी की संभावना कमजोर है। स्थानीय मंडी मे शकर की आवकें लगभग 8–10

दलहनी, तिलहनी फसलों के रकबे में बढ़ोत्तरी

भारत तिलहनी और दलहनी फसलों के मामले में अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। साल 2019–20 में हमने 68558.2 करोड़ रुपये का वनस्पति तेल इंपोर्ट किया। जबकि 10221.4 करोड़ रुपये की दालें इंपोर्ट की गईं। इसीलिए सरकार इन दोनों फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाकर इस पैसे को दूसरे देश जाने से बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। जिसके परिणाम इस बार रबी सीजन में दिखाई देने लगे हैं।

रबी सीजन 2021–22 में इन दोनों फसलों का रकबा काफी बढ़ गया है। तिलहनी फसलों की बुवाई इस साल 23.78 लाख हेक्टेयर में बढ़ी है, जबकि दलहनी फसलों के एरिया में 18.21 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, यह एक शुभ संकेत है। इससे खाद्य तेलों और दालों के इंपोर्ट में कमी आने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य तौर पर रबी सीजन में दालों का क्षेत्र 146.14 लाख हेक्टेयर होता है। जबकि मौजूदा रबी सीजन (2021–22) में 21 जनवरी तक इसका रकबा बढ़कर 164.35 लाख हेक्टेयर हो गया है।

इसी तरह तिलहनी फसलों का रकबा सामान्य तौर पर 77.38 लाख हेक्टेयर होता है जो अब बढ़कर रिकॉर्ड 101.16 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि के बाद रिकॉर्ड उत्पादन का भी अनुमान लगाया जा रहा है। एक कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों के रकबे में वृद्धि हुई है। इसकी बड़ी वजह अच्छा दाम है।

साल 2021 में सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले मार्केट में लगभग डबल रहा है। इसलिए इस बार किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार सरसों की खेती का दायरा 73 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 91 लाख हेक्टेयर हो गया है। राजस्थान, एमपी, यूपी और हरियाणा में इसके क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

अगर किसी फसल का अच्छा दाम मिलेगा तो किसान अपने आप उस फसल की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर दाम नहीं मिलेगा तो सरकार कुछ भी कर ले, कोई भी अभियान चला ले, किसान वही करेंगे जो उनके फायदे में होगा। खाद्य तेलों की घरेलू खपत मांग करीब 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन केवल 111.6 लाख टन है। यानी खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में करीब 56 फीसदी गैप है।

केंद्र सरकार का दावा है कि बीते पांच–छह साल में भारत ने दलहन उत्पादन को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन तक कर लिया है। वर्ष 2019–20 में भारत में 23.15 मिलियन टन दलहन उत्पादन हुआ, जो विश्व के कुल उत्पादन का 23.62 फीसदी है। इसके बावजूद भारत को विदेशों से दाल आयात करनी पड़ रही है। वर्ष 2050 तक लगभग 320 लाख टन दलहन की जरूरत होगी। ऐसे में अगर इसकी बुवाई का दायरा बढ़ा नहीं तो आयात पर निर्भरता कम नहीं होगी।

साल 2020–21 में भी नवंबर तक हम 7148.4 करोड़ रुपये की दालें इंपोर्ट कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 1951 में प्रति दिन प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता 60.7 ग्राम थी, जो 2020 में घटकर सिर्फ 47.9 ग्राम रह गई है। इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं।

चीनी के उत्पादन में 4.34% की बढ़ोत्तरी

चालू पेराई सीजन 2021–22 के पहले तीन महीनें पहली अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक चीनी का उत्पादन 4.34 फीसदी बढ़कर 115.55 लाख टन का हो चुका है जबकि पिछले पेराई सीजन में इस दौरान केवल 110.74 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था।

चालू पेराई सीजन में 492 चीनी मिलों में पेराई आरंभ हो चुकी है, जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में केवल 481 मिलों में ही पेराई आरंभ हो पाई थी। विश्व बाजार में दाम नीचे होने के कारण इस समय निर्यात सौदों में पैरिटी नहीं लग रही है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक, चालू पेराई सीजन में महाराष्ट्र में 31 दिसंबर 2021 तक 45.77 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 39.86 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। राज्य में 189 चीनी मिलों में पेराई आरंभ हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 179 चीनी मिलों में ही पेराई आरंभ हो पाई थी। उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सीजन में मिलों में देर से गन्ने की पेराई आरंभ हुई थी, जिस कारण राज्य में 31 दिसंबर तक 119 चीनी मिलों ने पेराई आरंभ कर दी है, जबकि पिछले सीजन की समान अवधि में 120 मिलों ने पेराई आरंभ कर दी थी। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक 30.90 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ है जोकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि के 33.66 लाख टन से कम है। कर्नाटक में 31 दिसंबर 21 तक 25.65 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में केवल 24.16 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था।

राज्य में चालू पेराई सीजन में 69 मिलों ने गन्ने की पेराई चल रही है। गुजरात में चालू पेराई सीजन में 31 दिसंबर 2021 तक 15 चीनी मिलों ने पेराई आरंभ कर दी है, तथा 3.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में राज्य की मिलों ने 3.35 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।

विश्व बाजार में रॉ–शुगर की कीमतों में आई गिरावट के कारण महीने भर से नए निर्यात सौदो नहीं हो रहे हैं, जबकि चालू पेराई सीजन में अभी तक कुल 38 से 40 लाख टन चीनी के निर्यात सौदों पहले हो चुके है।

विश्व बाजार में रॉ–शुगर के दाम 20 सेंट प्रति पाउंड से नीचे बने हुए हैं, जबकि इन भाव में निर्यात में पैरिटी नहीं लग रही है।

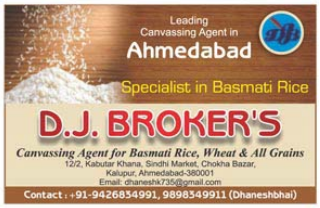

वर्ष 2021-22 में सरकार की धान खरीद अबतक 532.86 लाख टन

केंद्र ने चालू विपणन वर्ष 2021–22 के दौरान अब तक 532.86 लाख टन धान की खरीद की है, जिसमें अधिकतम खरीद पंजाब से की गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि, अब तक लगभग 64.07 लाख किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के रुप में 1,04,441.45 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। चालू विपणन सत्र में नौ जनवरी तक अब तक की गई कुल खरीद में से सर्वाधिक 186.85 लाख टन धान पंजाब से, उसके बाद 67.65 लाख टन छत्तीसगढ़ से, 65.54 लाख टन तेलंगाना से, 55.30 लाख टन हरियाणा से और 46.50 लाख टन उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है। धान विपणन का सत्र अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। विपणन सत्र 2020–21 के दौरान सरकार ने 1,69,133.26 करोड़ रुपए के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) मूल्य पर 895.83 लाख टन धान की खरीद की थी। सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ–साथ राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्य करती है।

सरकार एमएसपी के साथ किसानों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर धान और गेहूं खरीदती है। सरकार इस अनाज का इस्तेमाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पंजीकृत गरीब लाभार्थियों को रियायती दरों पर राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए करती है।

कोविड के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3086 लाख टन

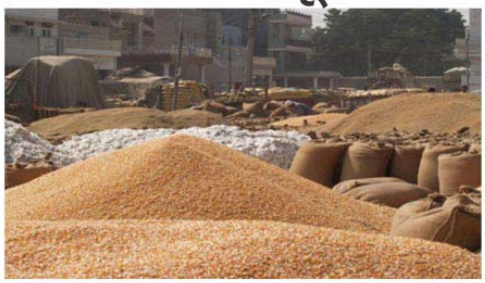

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि, कोविड के बावजूद किसानों ने काफी मेहनत की है, जिससे वर्ष 2020–21 में 3086.47 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। दलहन का 257. 19 एवं तिलहन का 361.01 लाख टन उत्पादन हुआ। यह भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कपास का उत्पादन 353.84 लाख गांठ होने का अनुमान है। जिसके कारण भारत का विश्व में पहले स्थान पर पहुंचना तय है। उत्पादन और उत्पादकता के मोर्चे पर, बागवानी क्षेत्र ने पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वो ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना है कि, ग्रीष्मकालीन फसलें न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं बल्कि रबी से खरीफ तक किसानों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करती हैं।

सरकार ने दलहन, तिलहन व पोषक–अनाज जैसी ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नई पहल की है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि कृषि उन्नत व लाभप्रद हो, उत्पादकता बढ़े व किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए। किसानों के सहयोग व सरकारी प्रयासों से चावल सहित जायद फसलों का रकबा 2017–18 में 29.71 लाख हेक्टेयर से 2.7 गुना बढ़कर 2020–21 में 80.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्री का कहना है कि, हमारे देश की विविध भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियां है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म ऋतु की फसलें ज्यादा से ज्यादा ली जानी चाहिए, ये किसानों को कम लागत व कम समय में अतिरिक्त आमदनी देने वाली होती हैं। राज्यों व किसानों के सहयोग से जायद फसलों का रकबा बढ़ रहा है। कृषि और किसानों के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ पूरी गंभीरता के साथ खड़ी है।

कृषि मंत्री का कहना है कि, पिछले सीजन में उर्वरकों के मामले में कुछ जगह एकाएक संकट की परिस्थितियां पैदा हुईं और कुछ लोगों ने अनावश्यक तूल दिया, पर केंद्र व राज्य सरकारें पहले से सजग थीं, इसलिए सबने मिलकर सूझबूझ से समस्या पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की, देश को जितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी, वह पूरी मात्रा केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास किया है। आगामी सीजन के लिए भी राज्य सरकारें एडवांस में पर्याप्त उर्वरक ले लें।

किसानों को फर्टिलाइजर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तोमर ने फर्टिलाइजर के अन्य विकल्पों का अधिकाधिक उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होना चाहिए, जिसके लिए एडवांस प्लानिंग की जरूरत है।

प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर: कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर फोकस किया है। उन्होंने इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य तय करते हुए निचले स्तर तक किसानों को ट्रेनिंग देने की बात कही। साथ ही किसानों के डाटाबेस को पूरा करने में राज्यों से विशेष रूचि लेने का आग्रह किया, ताकि इससे किसान लाभान्वित हों। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि तिलहन व दलहन उत्पादन बढ़ाने और इन 2 जिंसों में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना है कि, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से निचले स्तर तक किसानों के बीच पहुंचाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए।

सम्मेलन का उद्देश्य: जायद सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकारों के परामर्श से गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना है। ग्रीष्म 2021–22 के लिए दलहन–तिलहन व पोषक– अनाज के लिए राष्ट्रीय, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सम्मेलन में बताया गया कि 2020–21 में इन फसलों के तहत 40.85 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2021–22 के दौरान 52.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इसी तरह 21.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र दलहन और 13. 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तिलहन और 17.89 लाख हेक्टेयर पोषक–अनाज के तहत लाया जाएगा।

तुअर दाल की कीमतों में तेजी, कीमतें अभी और बढ़ने की उम्मीद

तुअर उत्पादन को खरीफ सीजन की आखिरी फसल के रूप में जाना जाता है। इस साल खरीफ पर कुदरत की मार पड़ी है और रबी के मौसम में भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि किसानों को तुअर के उत्पादन बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में अरहर की दाल आते ही दाल मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों की मांग तेजी से शुरू हो गई है। इसिलए किसान अब अनुमान लगा रहे हैं उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। अभी उत्पादन में गिरावट के बावजूद किसानों को अब बढ़ी हुई दरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है पिछले हफ्ते से जहां तुअर की आवक बढ़ी है, वहीं कीमतों में सुधार से किसानों का उत्साह भी बढ़ा है।

किसानों को उम्मीद हैं कि सीजन के आखिरी चरण में खरीफ सोयाबीन,कपास और अब तुअर के दाम बढ़ने से उत्पादन में गिरावट कम होगी। तुअर की कटाई अपने अंतिम चरण में है, किसान फसल कटाई के तुरंत बाद इसे बेचने के बजाय सोयाबीन और कपास जैसे भंडारण के साथ प्रयोग कर रहे हैं सीज़न की शुरुआत से पहले, तुअर की कीमत 6,000 से कम थी, लेकीन यह पिछले सप्ताह में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई हैं। इसलिए वर्तमान में तुअर का लेनदेन 5 हजार 800 से 6 हजार 500 रुपए तक हुआ हैं दरों में यह बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत की बात है। हालांकि के कम दरों में हो रहा हैं लेकिन किसान खुश हैं और आगे दाम बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

मौसम की शुरुआत और कृषि चीज़ों के आगमन के साथ, पहले चरण में दरों में गिरावट आती है। लेकिन तुअर के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आवक शुरू होते ही दाल मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों की ओर से मांग शुरू हो गई है। राज्य के अकोला, लातूर और अमरावती बाजारों में भी यही स्थिति बानी हुई हैं इसलिए रेट में सुधार हो रहा है। नई तुअर का आगमन अब शुरू हो गया है और जैसे–जैसे मांग भी बढ़ रही है, किसानों का उत्साह भी बढ़ता दिख रहा हैं।

नेफेड द्वारा राज्य के 186 केंद्रों पर तुअर की खरीद की जा रही हैं सीजन शुरू होने से पहले रेट कम होने के कारण किसानों ने केंद्र शुरू करने की मांग की थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। खुले बाजार में तुअर की कीमत कम से कम 6,000 होती हैं इतना ही नहीं इसके बढ़ने से किसान बिना किसी औपचारिकता के सीधे खुले बाजार में तुअर बेच रहे हैं इसके अलावा, यह अभी सीजन की शुरुआत हैं व्यापारियों के मुताबिक, सब कुछ तुअर के घटते उत्पादन और बढ़ती मांग पर निर्भर करता हैं।

स्वामी, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक: टी. आर. अरोड़ा द्वारा व्यापार एक्सप्रैस के लिए 2718, गली नं. 5, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा बालाजी आफसैट उत्पनपुर 1/11884, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से मुद्रित। संपादक-टी. आर. अरोड़ा